The Hindu- 05- January-2022

Constitutional validity of Dam Safety Act challenged in HC

Legislation blatantly usurps States' power, says DMK MP

MOHAMED IMRANULLAH S.
CHENNAI

Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) Lok Sabha member S. Ramalingam, representing Mayiladuthurai constituency in Tamil Nadu, has moved the Madras High Court challenging the constitutional validity of the Dam Safety Act, 2021 on the grounds that it goes against federalism and is beyond the legislative competence of the Centre.

Acting Chief Justice Munishwar Nath Bhandari and Justice P.D. Audikesavalu on Tuesday accepted a request made by senior counsel P. Wilson for an early hearing of the case and directed the Registry to list the matter for January 10.

Counsel said he would, by then, serve papers on Additional Solicitor General R. Sankaranarayanan.

In an affidavit filed in support of his petition, the Member of Parliament wrote: "The impugned (under challenge) Act is a legislation passed by the Union through brute majority to blatantly usurp the States' power in broad day light when legislators like myself were helpless to prevent the violence done to the Constitution."

Vague definitions

Mr. Ramalingam contended that certain terms, including the word 'dam' in the Act, had been deliberately defined vaguely to give unbridled power to the Centre to treat any dam as a 'specified dam'.

Mr. Ramalingam feared that if the definitions were accepted, almost all the dams in the country would fall under the purview of the Act.

The Indian Express- 05- January-2022

As Polavaram project costs jump, Andhra CM seeks PM's help

SREENIVAS JANYALA
HYDERABAD, JANUARY 4

THE ESTIMATED cost of the Polavaram multipurpose irrigation project in Andhra Pradesh has jumped to Rs 55,657 crore at 2017-18 rates, according to Chief Minister YS Jagan Mohan Reddy's request to Prime Minister Narendra Modi for approval.

The project's estimated cost as per 2013-14 prices was approximately Rs 20,400 crore. The revised estimate includes a drinking water supply component of Rs 4,000 crore. "The revised estimates include increasing capacities of the right and left main canals, Rehabilitation & Resettlement (R&R), land acquisition, and drinking water supply pipelines," Minister for Water Resources P Anil Kumar said.

Reddy also requested PM Modi for the release of pending payments of Rs 2,100 crore already incurred by the state towards the Polavaram project.

The Rs 55,657-crore estimation was mentioned in a revised Detailed Project Report-2, prepared by the state's Water Resources Department. In August last year, Union Minister for Jal Shakti, Gajendra Singh Shekhawat said his ministry had accepted the earlier revised cost estimate of Rs 47,726 crore, although the Ministry of Finance is yet to accept it.

The Chief Minister met Prime Minister Modi in New Delhi on Monday evening.

Hindustan- 05- January-2022

केंद्रीय जल आयोग उन्नत चेतावनी प्रणाली स्थापित करेगा

हिमालयी क्षेत्र में ग्लेशियर झील की निगरानी होगी

योजना

नई दिल्ली | एजेंसी

जल शक्ति मंत्रालय ने ग्लेशियर झील की निगरानी के लिए हिमालयी क्षेत्र में ह्यउन्नत चेतावनी प्रणालीह्ल स्थापित करने का प्रस्ताव तैयार किया है जिसे वर्ष 2026 तक चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जाएगा ।

मंत्रालय के एक अधिकारी ने को बताया कि केंद्रीय जल आयोग ने हिमालयी क्षेत्र में नदी प्रणाली के ऊपरी इलाकों में उन्नत चेतावनी प्रणाली स्थापित करने का प्रस्ताव तैयार किया है। इस पर करीब 95 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है।

प्रस्तावित योजना के अनुसार, प्रथम चरण में पहले दो वर्ष की अवधि के दौरान नदी प्रणाली के ऊपरी क्षेत्र में सायरन, सेंसर एवं अन्य उपकरण लगाए जाएंगे। इसके माध्यम से, खतरे की स्थिति में कुछ ही घंटों में स्थानीय निवासियों को चेतावनी दी जा सकेगी ताकि ग्लेशियर झील के टूटने पर लोगों को बचाया जा सके। उन्होंने बताया कि इस अवधि में 0.25 हेक्टेयर से अधिक आकार की ग्लेशियर झीलों की सूची तैयारी की जाएगी और मानसून की अवधि में 10 हेक्टेयर से बड़े आकार की सभी ग्लेशियर झीलों की मासिक आधार पर निगरानी की जाएगी ।

अधिकारी के अनुसार, इस प्रस्ताव के दूसरे चरण में 2 से 5 वर्ष की अवधि में उपग्रह जानकारी एवं भू सत्यापन के आधार पर अतिसंवेदनशील झीलों की सूची तैयार की जाएगी, तथा इन झीलों की निगरानी वर्तमान मासिक से बढ़ाकर साप्ताहिक की जाएगी। साथ ही, चिन्हित ग्लेशियर झीलों के संबंध में समय-समय पर मॉडल तैयार कर, आवश्यक होने पर अतिरिक्त सेंसर या उपकरण स्थापित किए जाएंगे।

50 हेक्टेयर से अधिक आकार की 477 हिमनद झीलें

भारत में 50 हेक्टेयर से अधिक आकार की 477 हिमनद झीलें हैं। जलशक्ति विभाग इनके आकार में असामान्य वृद्धि के बारे में चेतावनी देता है। भारत में लगभग 2038 झीलें 10 हेक्टेयर की हैं जिनकी निगरानी के लिए योजना बनाई जा रही है। उत्तराखंड में हिमखंड टूटने के कारण सात फरवरी 2021 को अचानक आई बाढ़ की घटना की संसद की एक स्थायी समिति ने समीक्षा की थी और हिमालयी क्षेत्र में ऊपरी इलाकों मे चेतावनी प्रणाली स्थापित करने की जरूरत पर जोर दिया था।

Haribhoomi- 05- January-2022

नव वर्ष में सबको नल से मिले जल

जल जीवन मिशन

अलका आर्य

जल जीवन मिशन अब जन आंदोलन के रूप में चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के 'सबका साथ, सब का विकास, सब का विश्वास, सब का प्रयास ' विजन के सिद्धांत का पालन करते हुए इस मिशन का आदर्श वाक्य है कि 'कोई भी छूटे नहीं' और मुल्क में हर ग्रामीण परिवार को नल के पानी का कनेक्शन दिया जाए। सिर्फ पानी ही उपलब्ध नहीं कराया जाए बल्कि पानी की गुणवत्ता पर निगरानी रखने की भी व्यवस्था की गई है। फील्ड टेस्ट किट का इस्तेमाल करके पानी की गुणवत्ता का परीक्षण करने क लिए 8 .5 लाख से अधिक महिला स्वयसेवकों को प्रशिक्षित किया गया है। जल जीवन मिशन का लक्ष्य 2024 तक मुल्क के हर ग्रामीण घर में नल से शुद्ध पेय जल पहुंचाना है।

पानी की समस्या को अक्सर एक सामाजिक समस्या के तौर पर देखा जाता है, जिसके स्वास्थ्य पर तात्कालिक व दूरगामी प्रभाव की पुष्टि कई अध्ययन भी करते हैं। मुल्क में पानी की कमी की समस्या एक गंभीर संकट है और इसके समाधान के लिए भारत सरकार न केवल मुल्क के भीतर बल्कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी इस मुद्दे को उठाने के लिए पहल करती नजर आ रही है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन (जे.जे.एम) की घोषणा की थी, इस मिशन के तहत मुल्क के सभी ग्रामीण घरों में यानी 19.22 करोड़ घरों में 2024 तक नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, मगर साथ ही साथ जल-स्रोतों की निरंतरता बनाए रखना भी इसका अनिवार्य हिस्सा है। इसके अंतगर्त वर्षाजल संचयन और जल संरक्षण के जरिए जल-स्रोतों के पुनर्भरण को सुनिश्चित किया जाता है तथा ग्रेवॉटर प्रबंधन के द्वारा गंदले पानी का पुनरुपयोग किया जाता है। नव वर्ष 2022 सरकार की प्राथमिकता है कि सबको नल से जल मिले।

वर्ष 2019 में मिशन की शुरुआत में मुल्क के 19.22 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से केवल 3.23 करोड़ (17 फीसदी) के पास नल जल की आपूर्ति थी। कोविड-19 महामारी और उसके कारण लगने वाले लॉकडाउन का असर तकरीबन हरेक गतिविधि पर पड़ा। जल जीवन मिशन का कार्य भी कुछ हद तक प्रभावित हुआ, लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद इस मिशन के तहत बीते 28 महीनों में 5.44 करोड़ से अधिक ग्रामीण घरों में नल से जल आपूर्ति शुरू हो चुकी है। आंकड़े महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि आंकड़े सुधार करने के साथ-साथ कार्यक्रमों के प्रदर्शन को आंकने का एक मौका मुहैया कराते हैं। बहरहाल जे.जे.एम के आंकड़ों बावत अपर सचिव व जल जीवन मिशन के निदेशक भरत लाल के अनुसार-वर्तमान में 8.67 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल जल उपलब्ध कराया गया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि मुल्क के तीन राज्य तेलंगाना, हरियाणा व गोवा और तीन केंद्र शसित प्रदेशों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा और नगर हवेली और दमन दीव, पुडुचेरी के सभी ग्रामीण घरों में नल जल की आपूर्ति की गई है शेष राज्यों व केंद्रशसित प्रदेशों में भी कार्य प्रगति पर है।'

वैसे भारत के मानचित्र पर ग्रामीण इलाकों के घरों में नल जल आपूर्ति को लेकर निगाह डालें तो 15 अगस्त 2019 की स्थिति व 30 नवंबर 2021 की स्थिति के फर्क को रंगों के जरिए समझा जा सकता है। इस दिशा में हो रही प्रगति साफ पता चलती है, लेकिन फिर भी चिंता बनी हुई है। घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करने के मामले में विभिन्न राज्यों की 30 नवंबर 2021 तक तुलनात्मक स्थिति बोलती है कि मुल्क का सबसे बड़ा राज्य जिसकी आबादी करीब 23 करोड़ है, वह जल जीवन मिशन में सबसे पीछे है। यहां ग्रामीण घरों में नल जल आपूर्ति का आंकड़ा दस प्रतिशत से थोड़ा ही ऊपर है। छत्तीसगढ़, प.बंगाल, झारखंड उत्तरप्रदेश से थोड़ा बेहतर प्रदर्शन करते दिखाए गए हैं। राजस्थान में यह आंकड़ा 30 प्रतिशत को छू गया है। उत्तरप्रदेश, छत्तीसगढ़, प.बंगाल,

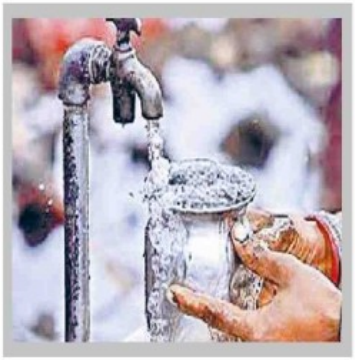

झारखंड और राजस्थान को लाल रंग में दर्शाया गया है। बेशक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी 16 नवंबर को उत्तरप्रदेश में 'पूर्वांचल एक्सप्रेस वे' के उदघाटन के मौके पर कहा कि सिर्फ दो साल ही में यूपी सरकार ने करीब-करीब 30 लाख ग्रामीण परिवारों को नल से जल पहुंचा दिया है,और इस वर्ष लाखों बहनों को अपने घर पर ही शुद्ध पेयजल देने के लिए डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।'

19 नवंबर को ही प्रधानमंत्री ने उत्तरप्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में महोबा में एक कार्यक्रम में राज्य के इस सूखे इलाके में पानी की कमी की चिंता पर वहां की जनता को यह आश्वासन दिया 'यहां की माताओं-बहनों की सबसे बड़ी मुश्किल को दूर करने के लिए, बुंदेलखंड में जल जीवन मिशन के तहत भी तेजी से काम हो रहा है। बुंदेलखंड और साथ-साथ विंध्यांचल में, पाइप से हर घर में पानी पहुंचे, इसके लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है।' संभवतः इस अभियान के सकारात्मक नतीजे आने वाले कुछ महीनों में नजर आएं। गुजरात, बिहार और हिमाचल प्रदेश करीब 90 फीसदी लक्ष्य को छूने वाले राज्य हैं। पंजाब इनसे आगे खड़ा नजर आता है। पंजाब ने 90 फीसदी ग्रामीण घरों में नल जल आपूर्ति कर दी है। पंजाब का पड़ोसी हरियाणा 100 फीसदी नल जल आपूर्ति के साथ पंजाब से आगे निकल गया है। वैसे जल जीवन मिशन जैसे सामाजिक आंदोलन के तहत बच्चों के स्वास्थ्य और उनकी देखभाल पर ध्यान केंद्रित करते हुए स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों मे नल से शुद्ध जल की आपूर्ति को प्राथमिकता के आधार पर लागू किया जा रहा है। इसके तहत अब तक 8.33 लाख यानी 81.33 प्रतिशत स्कूलों और 8.76 लाख यानी 78.48 प्रतिशत आंगनबाड़ी केंद्रों में नल से जल की व्यवस्था कर दी गई है, जिसमें शौचालयों में नल से जल की सुविधा भी शमिल है। यूनिसेफ इंडिया के वॉश के प्रमुख निकोलस ओस्बर्ट का मानना है कि जल जीवन मिशन विशेष तौर पर दूषित जल से होने वाली बाल मौतों को कम करने में अहम भूमिका निभा सकता है। इसमें बच्चों व महिलाओं की जिंदगी को बेहतर बनाने की संभावना है।

जल जीवन मिशन अब जन आंदोलन के रूप में चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के 'सबका साथ, सब का विकास, सब का विश्वास, सब का प्रयास ' विजन के सिद्धांत का पालन करते हुए इस मिशन का आदर्श वाक्य है कि 'कोई भी छूटे नहीं' और मुल्क में हर ग्रामीण परिवार को नल के पानी का कनेक्शन दिया जाए। सिर्फ पानी ही उपलब्ध नहीं कराया जाए बल्कि पानी की गुणवत्ता पर निगरानी रखने की भी व्यवस्था की गई है। फील्ड टेस्ट किट का इस्तेमाल करके पानी की गुणवत्ता का परीक्षण करने क लिए 8.5 लाख से अधिक महिला स्वयसेवकों को प्रशिक्षित किया गया है। वे नमूने इकट्ठे कर पानी की गुणवत्ता का परीक्षण करते हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आपूर्ति किया जा रहा जल निर्धारित मानकों के अनुसार है या नहीं। आज, मुल्क में 2,000 से अधिक जल परीक्षण प्रयोगशालाए हैं जो पानी की गुणवत्ता का परीक्षण करने के लिए मामूली कीमत पर जनता के लिए उपलब्ध हैं। जल जीवन मिशन के तहत सरकार का लक्ष्य 2024 तक मुल्क के हर ग्रामीण घर में नल से शुद्ध पेय जल पहुंचाना है। मुल्क के सुदूर-दुर्गम गांवों तक नल पेय जल पहुंचाने के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। हाल ही में लेह के जिला प्रशासन ने जिले के ऊंचे पर्वतीय दुर्गम और सुदूर से सुदूर इलाकों में स्थित गांवों में जल जीवन मिशन के कार्यों के वास्ते इस्तेमाल होने वाले पानी के पाइपों और अन्य सामग्री को पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद ली। जैसे-जैसे जल जीवन मिशन की रफ्तार और तेज होगी, वैसे-वैसे इस मिशन का आदर्श वाक्य' कोई भी छूटे नहीं 'चरितार्थ होने के करीब पहुंचता नजर आएगा।

(ये लेखक के अपने विचार हैं।)

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया edit@haribhoomi.com पर दे सकते हैं।

Amar Ujala- 05- January-2022

संवेदनशील ग्लेशियरों की होगी साप्ताहिक निगरानी

नई दिल्ली। संसद की स्थायी समिति की सिफारिश के बाद जल शक्ति मंत्रालय ने हिमालयी क्षेत्र के ऊपरी इलाकों में चेतावनी प्रणाली स्थापित करने का काम शुरू कर दिया है। 7 फरवरी 2021 को उत्तराखंड में बाढ़ के कहर के बाद समिति ने ग्लेशियरों की निगरानी की जरूरत बताई थी। देश में 50 हेक्टेयर से ज्यादा आकार के 477 हिमनद हैं। मंत्रालय ने उन्नत चेतावनी प्रणाली स्थापित करने का प्रस्ताव तैयार किया है। इसे क्रमबद्ध ढंग से 2026 तक लागू कराया जाएगा। इसका जिम्मा केंद्रीय जल आयोग संभालेगा। ब्यूरो